दैनिक जागरण
शिखर की शुरुआत भी शून्य से ही होती है

पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की जरूरत

संजय गुप्त

चूंकि बालाकोट हमले के बाद विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है इसलिए इसका लाभ उठाया जाना चाहिए और मसूद अजहर पर पाबंदी के बाद भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहिए

लगभग एक दशक के प्रयासों और खासकर मोदी सरकार की कूटनीतिक सक्रियता के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जैश ए मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर पाबंदी लगा दी। इसी के साथ वह अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित हो गया। उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में इतना समय इसलिए लगा, क्योंकि चीन रोड़ा बना हुआ था। वह इस आतंकी सरगना पर पाबंदी लगाने में भारत और अन्य देशों की कोशिश को कई बार नाकाम कर चुका था। चीन सुरक्षा परिषद में अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करके एक ओर जहां पाकिस्तान की ढाल बना हुआ था वहीं भारतीय हितों की अनदेखी भी कर रहा था। उसके इस रवैये के चलते भारत से रिश्तों में तल्खी भी आई। यह तो चीन ही जाने कि वह किस आधार पर इस आतंकी सरगना पर पाबंदी लगाने में तकनीकी बाधा उत्पन्न कर रहा था, लेकिन उसकी अड़ंगेबाजी भारतीय हितों के खिलाफ थी। शायद पाकिस्तान का अंध समर्थन करने की जिद में वह इसकी भी अनदेखी कर रहा था कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि दागदार हो रही। आखिरकार वह भारत के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों के कूटनीतिक दबाव में झुका, लेकिन इसका अंदेशा अभी भी बना हुआ है कि वह पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतों की अनदेखी कर आगे भी उसका बचाव करेगा।

मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी लगने का अर्थ है उसकी आवाजाही पर रोक, संपत्तियों की जब्ती और उसके हथियार रखने पर प्रतिबंध। सुरक्षा परिषद के फैसले के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि उसने ये सारे कदम उठा लिए हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कायदे से मसूद अजहर पर पाबंदी की मांग तभी मान ली जानी चाहिए थी जब 2009 में पहली बार इसकी मांग उठी थी, क्योंकि उसका संगठन प्रतिबंधित कर दिया गया था। मसूद अजहर को अपहृत भारतीय विमान के यात्रियों के बदले रिहा किया गया था। संसद के साथ पठानकोट एयरबेस पर हमले में भी उसका हाथ रहा। पुलवामा का हमलावर भी जैश सदस्य था। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इस हमलावर को पाकिस्तान से मदद मिली। मसूद अजहर भारत में आतंक फैलाने में इसीलिए समर्थ बना रहा, क्योंकि उसकी पीठ पर पाकिस्तानी सेना का हाथ था। पाकिस्तानी सेना कश्मीर में भारत के खिलाफ जो छद्म युद्ध छेड़े हुए है उसमें उसे जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठन उसका साथ देते हैं। पाकिस्तानी सेना भारत से इसलिए खुन्नस खाती है, क्योंकि वह भारत के हाथों बार-बार पराजित हुई है। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान की असली सत्ता उसके पास ही है। चूंकि पाकिस्तानी सेना भारत से बदला लेने की मानसिकता से ग्रस्त है इसलिए इसके आसार नहीं कि मसूद अजहर पर पाबंदी लग जाने के बाद कश्मीर में पाकिस्तानी पोषित आतंकियों की घुसपैठ में कमी आएगी। स्पष्ट है कि भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान आसानी से सही रास्ते पर आ जाएगा।

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस उम्मीद में पाकिस्तान के प्रति दोस्ताना रवैया दिखाया था कि वह शांति की भाषा समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार तो इस हालत में ही नहीं कि वह अपनी सेना के दबाव से मुक्त हो सके। इस पर आश्चर्य नहीं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना की कठपुतली माना जाता है। उड़ी हमले के बाद मोदी सरकार ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक का। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक का पाकिस्तान पर गहरा असर हुआ है। वह अब तक सहमा हुआ है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि अब पाकिस्तान के प्रति भारत की रणनीति क्या होगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि अगर मोदी सरकार फिर सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके खिलाफ सख्ती बरतने की नीति पर चलते रहेंगे। यह आवश्यक भी है, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता चलना ही चाहिए कि अब भारत उसकी आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दबाव बनाने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का साथ लेने के साथ ही चीन के रवैये को लेकर सतर्क भी रहना होगा। चूंकि बालाकोट हमले के बाद विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है इसलिए इसका लाभ उठाया जाना चाहिए।

इसमें दो राय नहीं कि मसूद अजहर पर पाबंदी लगना एक बड़ी सफलता है, लेकिन इसके बावजूद आवश्यक यह है कि भारत पाक की गतिविधियों से सतर्क रहे। उसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ अन्य आतंकी गुटों से भी सावधान रहना होगा। पहले श्रीलंका में भीषण आतंकी हमला और फिर इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन आइएस के सरगना का वीडियो सामने आना यही बताता है कि भारत को कहीं अधिक चौकन्ना रहना चाहिए। भारत को आतंकी संगठनों से सतर्क रहने के साथ ही उनकी गतिविधियों के बारे में सटीक खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान की भी कोशिश करनी चाहिए और उनके धन स्रोतों पर लगाम लगाने की भी। हालांकि मसूद अजहर पर पाबंदी के बाद अमेरिका ने पाक को नए सिरे से चेताया है, लेकिन भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि वह आतंकियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई करने में माहिर है।

इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं और तमाम अन्य मुद्दों के साथ यह बात भी चर्चा में है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर एयर स्ट्राइक। भाजपा इन दोनों सैन्य अभियानों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रही है। इसी के साथ वह विपक्ष और खासकर कांग्रेस को इसके लिए कठघरे में खड़ा कर रही है कि उसने सत्ता में रहते समय आतंकवाद का डटकर मुकाबला नहीं किया। चुनाव प्रचार में भाजपा नेता मसूद अजहर पर पाबंदी का भी जिक्र कर रहे हैं। इस आतंकी सरगना पर पाबंदी भारत की एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। आम तौर पर इसका सभी ने स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस यह भी उल्लेख कर रही है कि एक समय भाजपा सरकार ने ही इस आतंकी सरगना को रिहा किया था।

कांग्रेस का यह भी दावा है कि उसके समय भी कम से कम छह सर्जिकल स्ट्राइक की गईं। कांग्रेस का यह दावा उसकी हताशा का ही परिचायक है। कांग्रेस एक ओर तो यह कह रही है कि सेना के पराक्रम का ढिंढोरा नहीं पीटा जाना चाहिए और दूसरी ओर वह छह सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करके ठीक यही काम कर रही है। समझना कठिन है कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी देश-दुनिया को क्यों नहीं दी? सवाल यह भी है कि इस समय छह सर्जिकल स्ट्राइक के दावे का क्या मतलब? क्या कांग्रेस को यह पता नहीं कि जब कभी इस तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो जनता का मनोबल बढ़ता है? यह वही कांग्रेस है जिसका यह कहना रहा है कि सरकार को सेना की कार्रवाई का बखान नहीं करना चाहिए। कम से कम उसे तो यह पता होना चाहिए कि सेना सरकार की अनुमति से ही किसी अन्य देश में कोई कार्रवाई करती है और इस तरह की कार्रवाई का एक बड़ा मकसद शत्रु देश को सख्त संदेश देना होता है।

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

आतंक की आहट

श्रीलंका के सेना प्रमुख महेश सेनानायके का यह दावा भारत की चिंता बढ़ाने वाला है कि उनके यहां भीषण हमले करने वाले आतंकी कश्मीर, कर्नाटक और केरल से आए थे। निःसंदेह इस दावे की जांच-परख करनी होगी, क्योंकि सेनानायके यह नहीं स्पष्ट कर सके हैं कि नेशनल तौहीद जमात के आतंकी किस खास मकसद से भारत आए थे? उन्हें यह अंदेशा है कि आतंकी प्रशिक्षण पाने के लिए कश्मीर या केरल आए होंगे। उनके दावे की सच्चाई जो भी हो, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि श्रीलंका के नेशनल तौहीद जमात जैसा एक संगठन तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु तौहीद जमात नामक यह संगठन अपने अतिवादी विचारों के लिए जाना जाता है। यह संगठन सड़कों पर उतरकर कश्मीर को स्वतंत्र करने की मांग करने के साथ ही भारत सरकार पर कश्मीर में फलस्तीन जैसे हालात पैदा करने का भी आरोप लगा चुका है। बात केवल इतनी ही नहीं कि श्रीलंका और तमिलनाडु के इन दोनों अतिवादी संगठनों के नाम में समानता है, बल्कि यह भी है कि उनके विचार भी काफी मिलते हैं। माना जा रहा है कि नेशनल तौहीद जमात को भारत से धन भी मिलता रहा है। कहीं यह धन तमिलनाडु तौहीद जमात के जरिये तो नहीं भेजा गया? सच जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इन दोनों संगठनों में गहरे संपर्क-संबंध होने का संदेह है। चिंता की बात यह है कि दक्षिण भारत के कई नेता तमिलनाडु तौहीद जमात के प्रति नरम रवैया रखने के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है कि ये नेता देश की सुरक्षा से अधिक वोट बैंक की अपनी राजनीति को महत्व दे रहे हैं। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह के अतिवादी संगठनों को राजनीतिक संरक्षण और समर्थन न मिलने पाए। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केरल आइएस सरीखे खूंखार आतंकी संगठन के प्रति हमदर्दी रखने वाले तत्वों से मुक्त हो।

यह तथ्य गहन चिंता का कारण है कि केरल के कई युवक आइएस में शामिल होने के लिए सीरिया जा चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सीरिया जाने में नाकाम रहे तो जिहाद करने अफगानिस्तान चले गए। तमिलनाडु और केरल में जिहादी आतंक के प्रति लगाव रखने वाले तत्वों की संख्या बढ़ना शुभ संकेत नहीं। एक ऐसे समय जब श्रीलंका की तरह बांग्लादेश में भी आइएस और अलकायदा के समर्थक बढ़ते दिख रहे हैं तब भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। यह स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी है कि भारत सरकार श्रीलंका के उस दावे की तह तक जाने के ठोस कदम उठाए जिसके तहत कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर भारत आए थे। इसी के साथ उन कारणों की तह तक भी जाना होगा जिनके चलते श्रीलंका ने भारत की ओर से दी गई खुफिया सूचना की अनदेखी कर दी। भारत ने चर्चों में आतंकी हमले की एक तरह से सटीक सूचना दी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि श्रीलंका सरकार ने यह मानकर उसकी उपेक्षा कर दी कि इस सूचना का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना हो सकता है। अगर वास्तव में ऐसा है तो श्रीलंका ने एक तरह से आत्मघाती भूल की।

ठोस पहल जरूरी

उत्तराखंड में हाथियों का बढ़ता कुनबा सुकून देने वाला है, मगर बदली परिस्थितियों में इनके झुंड में कम होती संख्या हैरत में डाल रही है। एक दौर में यहां के हाथी बहुल क्षेत्रों में एक-एक झुंड में 90 तक की संख्या में हाथी दिखते थे, वह संख्या सिमटकर अब 32 से 40 के बीच आ गई है। उस पर गंगा के मैदानों में तो ये समूह और भी छोटे हो गए हैं। इस स्थिति के मद्देनजर फिजां में सवाल तैरना लाजिमी है कि आखिर इसकी वजह है क्या। वह भी तब जबकि उत्तराखंड में हाथियों के लिए यमुना से लेकर शारदा तक 6643.5 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल वन क्षेत्र उपलब्ध है। फिर भी झुंड में इनकी संख्या कम हो रही है, जबकि हाथी निरंतर बढ़ रहे हैं। वन महकमे के आंकड़ों पर ही गौर करें तो एक दशक पहले यहां हाथियों की संख्या 1582 थी, जिसमें वर्ष 2017 की गणना के अनुसार 257 का इजाफा हुआ। जाहिर है कि हाथियों की संख्या बढ़ने पर इनके झुंड भी बड़े-बड़े दिखने चाहिए थे, लेकिन झुंड में इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में प्रश्न उठना लाजिमी है कि कहीं जंगल में खाद्य श्रृंखला तो नहीं गड़बड़ा गई है या फिर बदली परिस्थितियों में हाथियों ने भी अपने झुंडों का आकार छोटा किया है। हालांकि, विशेषज्ञों की मानें तो यहां खाद्य श्रृंखला खासी सशक्त है। दिक्कत है तो सिर्फ यह कि हाथियों को यहां एक से दूसरे जंगल आने-जाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यही झुंड का आकार छोटा होने की वजह भी है। हाथी लंबी प्रवास यात्राएं करने वाला प्राणी हैं और इसके लिए वन क्षेत्र भी लंबे-चौड़े होने जरूरी हैं। यह वन क्षेत्र विभिन्न कारणों से सिमटे हैं। हाथियों की निर्बाध आवाजाही वाले गलियारों में मनुष्य ने बाधाएं खड़ी कर दी हैं। कहीं इनके परंपरागत रास्तों यानी गलियारों में मानव बस्तियां उग आई हैं तो कहीं सड़क व रेल मार्गों ने बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं। ऐसे में हाथी कुछ इलाकों तक ही छोटी-छोटी प्रवास यात्राएं कर पा रहे हैं और इसी का असर उनके झुंडों के आकार पर भी पड़ा है। हाथियों की आवाजाही को चिन्हित 11 गलियारे ही निर्बाध हो जाएं तो प्रवास यात्राओं के दौरान झुंडों में इनकी बड़ी संख्या दिखने लगेगी। साफ है कि इन गलियारों को खोलने के लिए सरकार को ठोस एवं प्रभावी पहल करनी होगी।

चुनावी चक्रव्यूह खत्म होने का इंतजार

हास्य-व्यंग्य

साकेत सूर्येश

माहौल बड़ा रोचक है। कांग्रेस प्रत्याशी सपा का, सपा प्रत्याशी कम्युनिस्टों का और कम्युनिस्ट कांग्रेसी का प्रचार कर रहे हैं

चुनाव अंतिम चरणों में है। नेता जनता के चरणों पर पड़े-पड़े उतावले हो रहे हैं। पत्रकारों और लेखकों पर वक्त बहुत भारी पड़ रहा है। अपने ज्ञान, मेधा और अनुमान को मन में दबाए पोल विषारद बैठे हैं। उनकी दुविधा को वही प्रेमी समझ सकता है जो प्रेमिका की रसोई मे आंटी जी को इम्प्रैस करने के लिए सिलेंडर लगा रहा हो। एक्जिट पोल पर लगे बैन के माहौल में चुनावी विश्लेषक 'जल बिन मछली' वाली अवस्था में लोट रहे हैं और अपने ज्ञान की एकाकी ज्वाला में तप्त होने को अभिशप्त हैं। जो समय रहते पोल पंडित के साथ-साथ नेताओं की दोहरी भूमिका में आ गए, वाणी संयोजन की कला का उपयोग करते हुए चैनलों के प्रिय बने हुए है, वहीं कुछ खालिस विश्लेषक परिणामों को लेकर जनता को भ्रमित करने के सुख से वंचित हैं। विरहणि का दुखी हृदय जिस प्रकार प्रेम परिणय के दिन याद करके दुखी होता है, उसी प्रकार पोलक समाज उन दिनों को याद करता है जब वे एक साथ प्रत्याशी के हारने और जीतने, दोनों का दावा पेश करके दोनों ओर सफलता का रुमाल धर देते थे।

लंबी चुनाव अवधि अपने साथ एक विचित्र सा निरुत्साह घेर लाई है। सब चक्रव्यूह घेरे जा चुके हैं। सब असत्य बोले जा चुके हैं। सब विवादों का दूध उबलकर पतीले के बाहर फैल चुका है। युवराज का गला चुनावी गर्मी में कुछ भी उगल रहा है। न्यायालय ने इस प्रकार राजनीति में लपेटे जाने का संज्ञान लेते हुए विरोध नेताजी को प्रेषित किया। नेता जी ने इस झूठे भाषण का ठीकरा एक आधुनिक युवा की भांति चुनावी गर्मी पर डालकर जान छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु न्याय व्यवस्था इस अति लंबे चुनाव के दौरान जनता की दिलचस्पी बनाए रखने को तत्पर है। मैं व्यक्तिगत तौर पर क्षमा देने और लेने की उस परंपरा का समर्थक हूं जिसमें निरर्थक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। इससे राजनीति में प्रवाह बना रहता है और चुनाव काल में लांग वीकेंड पर जाने को तत्पर जनता की राजनीति में रुचि बनी रहती है।

बंगाल की संप्रभु नेत्री भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक वीरतापूर्ण आचरण की पुनर्स्थापना के लिए कटिबद्ध हैं। वीरभोग्या वसुंधरा के अमर सिद्धांत को बूथ कैप्चरिंग के पुरुषार्थपूर्ण दिनों के इतने समय बाद आज के ईवीएम युग में भी जीवित रखने के लिए और आधुनिक भीरूता से भारतीय समाज को बाहर लाने के लिए समाज उनका सदैव अनुग्रहीत रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में माहौल बड़ा ही रोमांचक हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी सपा का प्रचार कर रहा है, सपा प्रत्याशी कम्युनिस्टों और कम्युनिस्ट कांग्रेस के नेता का। ऐसा लगता है कि जिसको जहां मंच खाली दिखता है, वह वहीं किसी भी प्रत्याशी के प्रचार में उतर जाता है। जनता भी हेलीकॉप्टर किसी का देखने जाती है और वोट किसी और प्रत्याशी को देती है। उग्र नेता भी गाली गलौज करके थक चुके हैं। क्रांतिकारी नेता अब अपनी सफलता के लिए प्रतिद्वंद्वी के नामांकन के निरस्त होने पर निर्भर हैं। बुजुर्ग कांग्रेस वोटकटवा बनकर संतुष्ट है। ऐसे बोरियत भरे माहौल में राहुल जी की नागरिकता जैसे प्रश्न उठाकर निरुत्साहित जनता में उत्साह फूंकने का प्रयास हो रहा है, किंतु निरहुआ का संगीत भी बोर हो रही जनता को उबारने में असमर्थ है।

भारत एक कमेटी प्रधान देश है। हर समस्या का समाधान हम कमेटी में ढूंढते हैं। इस विषय पर बाकायदा एक कमेटी नियुक्त है। अब एक ही संभावना बचती है कि उस कमेटी के कार्यकलाप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक अन्य कमेटी नियुक्त की जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में जनता का मन लगा रहे। भारतीय समाज में कमेटी का वही स्थान है जो रोमन साम्राज्य में ग्लेडिएटर परंपरा का था। समाजवाद का हंस बेगुसराय से दाना चुगकर पूंजीवाद के क्षितिज की ओर उड़ चला है। भूख पर भाषण देने के बाद पूंजीवाद से रोटी का प्रबंध किया जा रहा है। गरीब को गरीबी के महात्म्य का गायन सुनाने के बाद गायक-दल गुच्ची का चश्मा लगाकर अमेरिका पहुंच गया है। समाजवादी दलों के नेता आर्थिक स्थिति में पूंजीवादी नेताओं के समान संपन्नता प्राप्त कर चुके हैं। शीघ्र ही यह समानता सर्वहारा तक भी पहुंचेगी, ऐसी बुद्धिजीवियों में सर्वसम्मति है। अंतरराष्ट्रीयकरण के इस दौर मे प्रचारक और समर्थक अंतरराष्ट्रीय हो रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो आगे प्रत्याशी भी अंतरराष्ट्रीय निकलेंगे। वर्तमान में यही प्रतीक्षा है कि शीघ्रातिशीघ्र चुनावी चरण पूर्ण हों और नेतागण जनता के चरणों मे पड़े चारण की छद्म मुद्रा से बाहर आकर पुनः नेतासुलभ भ्रष्ट भाव धारण करें और लोकतंत्र अपने स्वाभाविक स्वरूप में लौटे।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | चुनावों के दौरान की गई बरामदगी का ब्योरा

स्रोत : भारत निर्वाचन आयोग

ऊर्जा

सार्थक जीवन

आजकल सभी वृद्धि और विकास के आकांक्षी बने हुए हैं। व्यक्ति से लेकर तक राष्ट्र तक सभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं। मगर विकास है क्या? क्या भौतिकता का प्रसार ही विकास का पर्याय है। हर एक के जीवन में भौतिक चमक-दमक। किसी के पास भौतिक साधनों का कोई अभाव नहीं। भौतिकता में आकंठ डूबा मनुष्य अब कुछ कदम भी पैदल नहीं चलना चाहता। उसके पास बड़े से बड़े मकान हों चाहें इसके लिए अगल-बगल में लगे वातावरण को स्वच्छ करने वाले पेड़ों को ही क्यों न काटना पड़ जाए।

आज का मनुष्य समाज में सबसे बड़ा दिखना चाहता है। सभी ओर होड़ मची है। मनुष्य नहीं देख पा रहा है कि हमें इस संसार में मानव जीवन किसलिए प्राप्त हुआ है। वह बाहर के प्रपंचमय जगत में आकर्षित होकर उलझ गया है। यहां पर शांत होकर धैर्यपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमें इस दिशा में सोच बढ़ानी होगी कि मानव जीवन मिलने के बाद हम बालक से युवा होते हैं। युवावस्था के बाद बुढ़ापा और फिर भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। भौतिक शरीर रहने तक ही सभी मानव इस जगत के सदस्य माने जाते हैं। शरीर समाप्त हो जाने के बाद इस जगह से पूर्ण रूप से नाता टूट जाता है। अब देखना होगा कि शरीर रहते हमने कैसे विकास को करने का प्रयास किया। भौतिक समृद्धि के लिए गिरते पड़ते रहे या आत्म-उन्नति के लिए भी कुछ प्रयत्नशील हुए। हमने अपने आंतरिक विकास के लिए कितनी तेजी दिखाई। आंतरिक विकास के बिना बाहरी विकास करते रहने से मनुष्य किसी एक स्थान पर जाकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद उसमें से जो रस प्राप्ति की प्रतीति हो रही थी, वह बंद हो जाती है। तब छटपटाहट बढ़ जाती है। यही स्थिति आज चारों ओर दिखाई पड़ रही है। वाह्य चमक-दमक के कारण आज का मानव विक्षिप्तता की ओर बढ़ा जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह विकास के पथ पर है अथवा विनाश के मुहाने पर। अब मनुष्य को अपनी वाह्य ऊर्जा को समेटकर आंतरिक चेतना को जगाना होगा। आंतरिक चेतना को जगाकर वाह्य क्रियाओं को निष्पादित करते हुए मानव सच्चे विकास की सही मंजिल को प्राप्त कर सकेगा। तभी जीवन सही मायनों में सार्थक होगा।

अशोक वाजपेयी

ब्रह्मांड के इतिहास की अहम कड़ी

मुकुल व्यास

वैज्ञानिकों की यह कोशिश उन सवालों के जवाब तलाशने की है कि हम कहां से आए हैं और ब्रह्मांड में हमारा स्थान कहां है

अरबों वर्ष पहले हमारे सौरमंडल के नजदीक दो न्यूट्रॉन तारों के बीच जबर्दस्त भिड़ंत हुई थी। पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुछ बहुमूल्य धातुओं का उद्गम संभवतः इसी टक्कर से हुआ था। गौरतलब है कि ब्लैकहोल्स के अलावा न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के सबसे सघन पदार्थ हैं। इनका अर्द्धव्यास बहुत कम होता है जो आम तौर पर 30 किलोमीटर तक होता है। न्यूट्रॉन कणों से भरपूर होने के कारण इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। उनकी उत्पत्ति उस समय होती है जब एक विशाल तारा अपना ईंधन खत्म होने के बाद खुद अपने ऊपर ढह जाता है। 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के खगोल वैज्ञानिक स्जाबॉक्स मार्का और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के खगोल वैज्ञानिक इमरे बार्तोस ने बताया कि 4.6 अरब वर्ष पहले दो न्यूट्रॉन तारों के बीच प्रचंड भिड़ंत हुई थी।

हमारे सौरमंडल के करीब हुई इस ब्रह्मांडीय घटना ने पृथ्वी की भारी धातुओं के करीब 0.3 प्रतिशत हिस्से को जन्म दिया। इन भारी धातुओं में सोना, प्लूटोनियम और यूरेनियम शामिल हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम लोग किसी न किसी रूप में इन धातुओं से जुड़े हुए हैं। बार्तोस ने कहा कि हमारे भीतर इन धातुओं का अंश मौजूद है। जैसे आयोडीन जो जीवन के लिए अनिवार्य है। विवाह की अंगूठी का भी हमारे ब्रह्मांड के इतिहास से गहरा संबंध है। अंगूठी में शामिल तत्व पृथ्वी और मानवता के इतिहास से भी पुराने हैं। अंगूठी का करीब 10 मिलीग्राम हिस्सा संभवतः 4.6 अरब वर्ष पहले ही बन चुका था। बार्तोस ने बताया कि आरंभिक सौरमंडल में बने उल्का पिंडों में रेडियोधर्मी आइसोटोप के अंश मौजूद हैं। दूसरे खगोल वैज्ञानिक मार्का का कहना है कि इन आइसोटोप में क्षय होता रहता है।

यह क्षय घड़ी के रूप में काम करता है जिसका उपयोग वैज्ञानिक आइसोटोप की उत्पत्ति के समय को पुनर्निर्मित करने के लिए कर सकते हैं। अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए बार्तोस और मार्का ने उल्कापिंडों की संरचना की तुलना मिल्की-वे आकाशगंगा के मॉडलों से की। उनका अनुमान है कि न्यूट्रॉन तारों की टक्कर पृथ्वी के निर्माण से करीब दस करोड़ वर्ष पहले हुई होगी। तारों की भिडंत की जगह हमारे सौरमंडल को जन्म देने वाले गैस के बादल से एक हजार प्रकाश वर्ष दूर थी। मार्का ने कहा कि आज यदि हमारे सौरमंडल से इतनी ही दूरी पर ऐसी घटना दोबारा घटित होती है तो उससे निकलने वाले रेडिएशन से समूचे आकाश की रोशनी फीकी पड़ जाएगी।

शोधकर्ताओं का खयाल है कि उनके अध्ययन से हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति और संरचना में शामिल समस्त प्रक्रियाओं पर नई रोशनी डालने में मदद मिलेगी। बार्तोस ने कहा कि इस अध्ययन से ब्रह्मांडीय गुत्थी को सुलझाने के लिए रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र जैसे विषयों में नए किस्म के शोध को बढ़ावा मिलेगा। मार्का का कहना है कि हमारे नतीजे मनुष्य के इस बुनियादी सवाल का उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि हम कहां से आए हैं और ब्रह्मांड में हमारा स्थान कहां है। अंतरिक्ष में पारलौकिक जीवन की तलाश के लिए चल रही खोज में वैज्ञानिकों के इस तरह के अध्ययन बहुत उपयोगी होते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

कांग्रेस की हताशा

राहुल गांधी भले ही चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देने की बात करते हों, लेकिन चुनाव के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में हताशा साफ नजर आ रही है। आम जनता के बीच गठबंधन और भाजपा की चर्चा तो है, लेकिन कांग्रेस की नहीं है। अमेठी, रायबरेली समेत जिन सीटों पर कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी चर्चा व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार की जरूर हो रही है, लेकिन पार्टी के रूप में कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस की हताशा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रायबरेली में सोनिया गांधी को जीतने के लिए सपा का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां सपा के मंच से प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी को जिताने की अपील की। बताया जाता है कि सपा के एक विधायक को इसके लिए बाकायदा अखिलेश यादव की ओर से निर्देश दिया गया था।

चुनावी संसाधन का संकट

देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा चुनाव का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां इसी आधार पर अपनी जीत तो विरोधी की हार का दावा करने लगी हैं। मगर इन दावों के बीच चुनाव के बचे हुए हिस्से की

राजरंग

बाजी और प्रबंधन को लेकर इनकी अपनी चुनौतियां भी हैं। मसलन कांग्रेस के कई उम्मीदवारों की चुनौती बूथ प्रबंधन के लिए संसाधन जुटाने की है। इसीलिए पार्टी के ऐसे प्रत्याशी जिनकी चुनावी खर्च की अपनी सीमाएं हैं, वे पार्टी के अलग-अलग बड़े नेताओं को बूथ प्रबंधन के खर्च का इंतजाम करने की गुहार लगा रहे हैं। वे तर्क दे रहे हैं कि सत्ताधारी भाजपा या राजग के उम्मीदवार चुनाव और बूथ प्रबंधन के लिए इतने संसाधन बहा रहे हैं कि उनका मुकाबला मुश्किल है। मगर कम से कम वोटिंग के दिन बूथ प्रबंधन कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी खर्च देना अपरिहार्य है। दिलचस्प यह है कि पार्टी की ओर से कुछ एक को थोड़ी बहुत मदद देकर कहा जा रहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार प्रबंधन चलाने में ही बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और वे अपने खर्च का प्रबंध खुद करें। पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों के सामने अब बेचारगी से जनता की ओर निहारने के अलावा विकल्प भी क्या है?

जेट के पायलटों का दर्द

जेट एयरवेज के बंद होने के कारण इन दिनों उसके कर्मचारियों के हाल बेहाल हो जाना स्वाभाविक ही है। शायद ही कोई उनके दुख-दर्द को समझ सकता हो। उनमें से कुछ को जो दूसरी विमानन कंपनियां ले भी रही हैं उनके प्रति इन कंपनियों का रवैया भी सही नहीं है। हाल में जेट के कुछ पायलटों ने एक दूसरी एयरलाइन में भर्ती के लिए इंटरव्यू दिया तो वहां भी उनकी खासी बेइज्जती की गई। वेतन के बारे में बात करते हुए इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने जेट के पायलट से कहा कि तुम इतने वेतन के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। हम तुम्हें इतना वेतन नहीं दे सकते। आखिर तुम मजबूरी में हमारे पास आए हो और तुम्हें नौकरी देकर हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इसलिए जितना वेतन और सुविधाएं मिलें चुपचाप स्वीकार कर लो। वरना तुम्हें लेना हमारी मजबूरी नहीं है। बेचारा जेट का पायलट खून के आंसू पीकर रह गया। विवशता में उसने नौकरी तो स्वीकार कर ली, लेकिन अपने साथियों को इस वाकये का ब्योरा देने से खुद को रोक नहीं सका। जेट की पायलट एसोसिएशन नेशनल एविएटर्स गिल्ड को जब इस बारे में पता चला तो उसने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए उक्त एयरलाइन के प्रबंधन के समक्ष अपना विरोध दर्ज करा दिया। अब वो एयरलाइन सफाई देते घूम रही है कि हो सकता है कि उक्त घटना में किसी अधिकारी विशेष ने अपने निजी विचार रखे हों। एयरलाइन जेट के पायलटों का सम्मान करती है।

दुविधा में नौकरशाही

नई सरकार बनने का वक्त जैसे-जैसे करीब आ रहा है, नौकरशाही भी सक्रिय होती जा रही है। नई सरकार के लिए एजेंडा तैयार करने का काम जोरों पर शुरू हो गया है, लेकिन नौकरशाही का एक वर्ग इस बात को लेकर भ्रम में है कि किन नीतियों व कार्यक्रमों को एजेंडे में रखा जाए। सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर ये अफसर लगातार मीडिया के लोगों और अन्य स्रोतों के संपर्क में हैं। ये अफसर इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि जो एजेंडा बने वह किसी की भी सरकार के कामकाज में फिट हो जाए। इसलिए वे ऐसी घोषणाओं को एजेंडे में आखिरी वक्त तक शामिल करने से रोके रखना चाहते हैं। हालांकि नौकरशाही का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने मौजूदा सरकार के कार्यक्रमों के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करनी भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि 23 मई के बाद उन्हें कौनसी रणनीति को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा?

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।